RNI NO. MPHIN/2022/85285
डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24
Email id: haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

वर्ष 02 अंक 11 | जनवरी 2024 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

चिंताजनक: पांच साल में 90 हजार हेक्टेयर जंगल खत्म

1980 के बाद से 10.6 लाख वन भूमि का गैर वनीय उपयोग के लिए डायवर्जन हुआ

88174 02860 (वन)। देश में पिछले पांच साल में करीब 90 हजार हेक्टेयर वन भूमि विकास कार्यों की भेंट चढ़ गई। लोकसभा में पेश किए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2018 से मार्च, 2023 के बीच सबसे अधिक वन भूमि सड़क और खनन के लिए ली गई है। साल 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनने के बाद से अब तक देशभर में 10 लाख 26 हजार हेक्टेयर वन भूमि का गैर वनीय उपयोग के लिए डायवर्जन हुआ।

यह भूमि दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्रफल से लगभग 7 गुना अधिक है। पिछले 15 साल में 3,05,756 हेक्टेयर वन भूमि गैर वन भूमि में बदली। 1990 में 1.27 लाख हेक्टेयर सबसे अधिक वन भूमि गैर वन भूमि में बदली थी। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बीच यह आंकड़े चिंताजनक है। जंगलों के बेहतर संरक्षण के लिए साल 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था। उदारीकरण से ठीक पहले साल 1990 में सर्वाधिक 1 लाख 27 हजार से अधिक वन भूमि का डायवर्जन हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा डायवर्जन साल 2000 में हुआ।

लगातार घटते से जंगलों से इनके वजूद पर सवाल खड़ा हो रहा है।

जबकि इस साल 1 लाख 16 हजार से अधिक वन भूमि गैर वनीय उपयोग के लिए डायवर्ट की गई है। 7 अगस्त 2023 को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि पिछले 15 वर्षों (2008.09 से 2022.23) में ,05,756 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन हुआ है। वहीं अगर पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो करीब 90 हजार हेक्टेयर वन भूमि अप्रैल 2018 से मार्च 2023 के बीच देशभर के 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे अधिक वन भूमि सड़क और खनन के लिए ली गई है। पिछले 5 सालों की बात करें तो इन सालों में 90 हजार हेक्टेयर वन भूमि का गैर वनीय उपयोग के लिए डायवर्जन हुआ है।

देखा जाए तो दुनिया भर के जंगल खतरे में है। साल 2022 में ही करीब 66 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल इंसानी फितरत की भेंट चढ़ गए। यानी हर मिनट में दुनिया भर में करीब 13 हेक्टेयर में फैले जंगल काटे जा रहे हैं। इसके लिए कृषि, पशुपालन, सोया की खेती, ताड़ के तेल का उत्पादन और छोटी जोत वाली खेती प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इनके साथ ही सड़कों का बिछता जाल, पेड़ों की व्यावसायिक रूप से हो रही कटाई भी इनको गंभीर नुकसान पहुंचा रही है।

इन राज्यों में कितनी वन भूमि बदली

- राजस्थान.2972.12 हेक्टेयर
- मध्यप्रदेश.19730.36 हेक्टेयर
- छत्तीसगढ़.2802.38 हेक्टेयर
- गुजरात.8064.76 हेक्टेयर
- नई दिल्ली.85.05 हेक्टेयर
- उत्तर प्रदेश.4090.64 हेक्टेयर
- पश्चिम बंगाल.621.68 हेक्टेयर
- महाराष्ट्र.2137.89 हेक्टेयर
- ओडिशा.13304.79 हेक्टेयर
- बिहार.1852.75 हेक्टेयर
- जम्मू.कश्मीर.450.65 हेक्टेयर
- तमिलनाडु.135.63 हेक्टेयर

इनके लिए भी ली गई वन भूमि

अस्पताल/ डिस्पेंसरी, पेयजल योजना, वनग्रामों का कन्वर्जन, उद्योग, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन, पुनर्वास, स्कूल, विद्युतीकरण।

पांच साल में वन भूमि का उपयोग

- सड़क.19,497 हेक्टेयर
- खनन .18,790 हेक्टेयर
- ट्रांसमिशन लाइन व सिंचाई .10 हजार हेक्टेयर
- रक्षा परियोजना.7,631 हेक्टेयर
- हाइड्रो परियोजना.6,218 हेक्टेयर
- रेल परियोजना. 4,770 हेक्टेयर का डायवर्जन हुआ है।

डिसक्लेमर: उपर व्यक्त विचार कार्टूनिस्ट के स्वयं के है।

हसदेव अरण्य में फोर्स लगाकर काटे जा रहे पेड़!

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 137 हेक्टेयर में फैले जंगल में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। आरोप है कि आने वाले दिनों में यहां 2ा50 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। ये पेड़ परसा ईस्ट और कांता बसन ।पीईकेबीद्ध कोयला खदान के लिए काटे जा रहे हैं। पीईकेबी को अडानी समूह द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया है। यह पेड फोर्स लगाकर मशीनों से काटे जा रहे है।

एक फिल्म निर्माता, पर्यावरण कार्यकर्ता और शोधकर्ता एकता ने एक प्रेस बयान में कहा कि जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र हसदेव जंगल में 170,000 हेक्टेयर में फैला है, जहां से छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारियों ने 15,000 से अधिक पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। यह जंगल हाथियों, भालू, सरीसृप और अन्य सहित जानवरों की कई प्रजातियों का घर है। साल और महुआ जैसे आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जो स्थानीय लोगों की आजीविका का भी साधन हैं। वे लोग इन पेड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। इन पेड़ों को काट दिया गया है, जिन्हें 100 से अधिक वर्षों से संरक्षित और संरक्षित किया गया है।

पेड़ों की आधिकारिक संख्या 15,307 होने का अनुमान है, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि झाड़ियों और झाड़ियों के रूप में सूचीबद्ध कई छोटे पेड़ों को भी काटा गया है। संभावना है कि वन विभाग के अधिकारी पहले ही 30,000 से अधिक पेड़ काट चुके हैं और आने वाले दिनों में 250,000 अन्य पेड़ काटने का खतरा मंडरा रहा है।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए विरोध जारी है, लेकिन आशंका है कि 841 हेक्टेयर में फैले परसा में पेड़ों की कटाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। पीईकेबी की कोयला खनन क्षमता क्रमशः 2 करोड़ टन प्रति वर्ष है। इनमें परसा में 50 लाख टन और कांटा में 70 लाख टन सालाना होगी। उन्होंने कहा इस प्रक्रिया में कुल आठ लाख पेड़ काटे जाएंगे। घने वन क्षेत्र के नीचे कुल पांच अरब टन कोयला होने का अनुमान है। आदिवासी और ग्रामीण बार.बार विरोध मार्च निकाल रहे हैं और अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और यहां तक कि उन्हें 2021 से वनों की कटाई करने से भी रोक रहे हैं, लेकिन अंततः अधिकारी 2022 में वनों की कटाई शुरू करने में कामयाब रहे।

एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनिक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रुप से प्रकाशित हो रहा है। अखबार की प्रतियां नियमित रुप से प्राप्त करने के लिए वार्षिक सदस्यता लेने, एजेंसी/ विज्ञापन प्रकाशन के लिए हमारे वाट्सअप नंबर(88174 02860) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है।

नोट: कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखे लेख प्रकाशन के लिए भी वाट्सअप नंबर पर भेज सकते है। आपके द्वारा भेजे गए लेख, शोधकार्य या कृषि के क्षेत्र में नई तकनिकी, सफलता हासिल करने संबंधित समाचार को भी प्रमुखता से प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे।

अजब– गजब: पैदावार बढ़ाने तैयार की इलेक्ट्रानिक मिट्टी, स्वीडन के वैज्ञानिको ने किया दावा

विदेशों किसानों के कृषि संसाधन हमारे देश से काफी विकसित और सोच में आगे होते है। किसान और इनके खेती बाड़ी करने के तौर तरीके तो होते ही है साथ ही यहां के वैज्ञानिक भी खेती में कई हैरान करने वाली नई तकनिकी खोज कर देते है जो समूचे विश्व में चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसी ही नई खोज स्वीडन के वैज्ञानिको ने की है जो हमारे देश में भी चर्चा में है।

हलधर किसान (विदेश)। यूरोपीयन देश स्वीडन के वैज्ञानिकों ने विद्युत सुचालक एक ऐसी मिट्टी विकसित की है, जिससे औसतन 15 दिन में जौ के पौधों की 50 प्रतिशत अधिक वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है। मिट्टी रहित खेती की इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स के रूप में जाना जाता है। इस विधि में ऐसी जड़ प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जिसे खेती के नए सब्सट्रेट (ऐसा पदार्थ या सतह जिस पर कोई पौधा बढ़ता है) के माध्यम से विद्युत रूप से उत्तेजित किया जाता है।

बहुत नियंत्रित परिवेश में उगा सकते हैं फसल

स्वीडन स्थित लिंकोपिंग विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एलेनी स्तावरिनिडौ ने कहा, दुनिया की आबादी बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है इसलिए यह स्पष्ट है कि हम खेती के केवल पहले से मौजूद तरीकों से पृथ्वी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम शहरों में भी बहुत नियंत्रित परिवेश में फसल उगा सकते है।

50 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़े पौधे

टीम ने हाइड्रोपोनिक खेती के अनुरूप एक विद्युत सुचालक खेती सब्सट्रेट विकसित कियाए जिसे वे ई.सॉइल कहते हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेजए पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि विद्युत सुचालक मिट्टी में उगाए गए जौ के पौधे 15 दिनों में तब 50 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़े जब उनकी जड़ों को विद्युतीय रूप से उत्तेजित किया गया।

बिना मिट्टी के उगते हैं हाइड्रोपोनिक खेती में फसल

हाइड्रोपोनिक खेती का मतलब है कि पौधे मिट्टी के बिना उगते हैं, उन्हें केवल पानीए पोषक तत्वों और ऐसे सब्सट्रेट की आवश्यकता होती है जिससे उनकी जड़ें जुड़ सकें। आमतौर पर अनाज को चारे के रूप में उपयोग के अलावा हाइड्रोपोनिक्स में नहीं उगाया जाता है। नवीनतम अध्ययन मेंए शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके जौ के पौधों की खेती की जा सकती है और विद्युत उत्तेजना के कारण उनकी विकास दर बेहतर होती है।

जैविक खेती में ऐसी मिली सफलता कि अब विदेशी शोधार्थी भी ले रहे टिप्स

राजस्थान के ग्राम चुंडियावाला गांव पहुंचे फ्रांस, स्वीडन व इंग्लैंड से कई विदेशी शोधार्थी

हलधर किसान (सफलता की कहानी)। राजस्थान का डूंगरपुर जिले के लीलवासा ग्राम पंचायत क्षेत्र के चुंडियावाडा गांव इन दिनों विदेशी पर्यटकों को बेहद लुभा रहा है। यह जमावड़ा क्रिसमस या नये साल का जश्न मनाने के लिये नही बल्कि आर्गेनिक खेती और पशुपालन के देशी गुर सीखने के लिए लगा रहा है। यहां गांव के ही ईश्वर सिंह राठौड़ के फार्म हॉउस पर यह विदेशी मेहमान रुके है।

ईश्वर सिंह वर्ष 2004 तक बड़े शहरों में कार्पोरेट जॉब करते थे, लेकिन लाखों का पैकेज की नौकरी छोड़कर अपने चुंडियावाड़ा गांव आ गए और करीब 18 बीघा जमीन पर फार्महाउस बनाकर जैविक खेती कर रहे है और आस.पास गांवों को ही नहीं, बल्कि विदेशी शोधार्थियों को भी जैविक खेती के गुर सिखा रहे हैं। विदेशी मेहमान स्टीवन व थॉमस का कहना है कि भारत की प्रकृति बहुत ही अच्छी है। गांवों में रहकर जैविक खेती, पशुओं का दूध दुहना, चारा डालना, फसल काटना आदि सब काम कर रहे है। जैविक खेती को समय की मांग बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उक्त संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि यहां के बारे में संस्था से ही पता चला हैए, जिसके बाद जैविक खेती व पशुपालन का कार्य सीखने चुंडियावाडा गांव आ गए है।

पिछले 17 वर्षों से विदेशी सैलानी फार्म हाउस पर पहुंच रहे है, 30 पश्चिमी देश के शोधार्थी जुड़े है, यहां जैविक खेती सीखने व सिखाने की परम्परा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों से जैविक खेती के गुर सीखने के लिए विदेशी यहां आते हैं, 16 वर्षों में 14 देशों से 150 से अधिक शोधार्थी यहां आ चुके हैं, जहां वो जैविक कृषि के गुर सीख रहे हैं और आज भी यह सिलसिला जारी है। दिसंबर माह में भी फ्रांस, स्वीडन व इंग्लैंड से कई विदेशी शोधार्थियों का चुंडियावाडा गांव पहुंचा है।

गेहूं की फसल पड़ने लगी है पीली तो करें यह उपाय

हलधर किसान (फसल प्रबंधन)। 88174 02860 रबी मौसम की प्रमुख फसलों में गेहूं की फसल शामिल है। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए कोहरा और अधिक ठंड बेहद कारगर मानी जाती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह ठंडे तापमान को पसंद करने वाली फसल है। देश के पंजाब,हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने इसकी व्यापक खेती की है। लेकिन कई क्षेत्रों में जनवरी माह के दौरान खेतों में गेहूं की पत्तियां पीली पड़ने की शिकायतें सामने आती रही है, जिससे किसान काफी चिंतित हो जात है, उन्हें समझ में नहीं आता कि इसका पीलापन होने का कारण क्या है? यह जानना बहुत जरूरी है कि गेहूं की निचली पत्तियां आखिरकार पीली क्यों हो रही हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? और इस समस्या से निदान कैसे मिलेगा? इस विषय पर कृषि वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है।

गेहूं की अच्छी बढ़ोतरी के लिए ठंडक होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडक की वजह से पहली सिंचाई और कहीं.कहीं पर दूसरी सिंचाई की वजह से खेत में पानी लग जाने से गेहूं की नीचे की पत्तियां पीली हो जाती है। सर्दी के मौसम में मिट्टी में सूक्ष्मजीवी गतिविधियां पौधे पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं और सूक्ष्मजीव जीव और पौधों के पोषक तत्वों के ग्रहण को लेकर एक अहम भूमिका निभाती हैं। सर्दियों में तापमान जब बहुत कम हो जाता है, अधिक ठंडे कारणों से पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। सूक्ष्मजीव की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं तापमान से सीधे जुड़ी हुई हैं। इस पर्यावरणीय कारक का मिट्टी में सूक्ष्मजीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जमीन से पौधों को पोषक तत्व लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्मजीव जमीन में पड़े नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपघटन करके

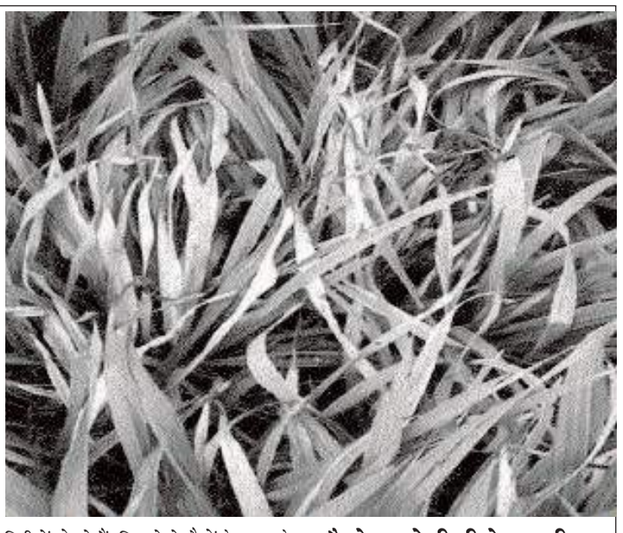

मिट्टी में छोड़ते हैं, जिससे वे पौधों के ग्रहण के लिए उपलब्ध हो पाते हैं।

गेहूं में पत्तियां क्यों होती हैं पीली?

वैज्ञानिको का कहना है कि जैसे ही अधिक सर्दी शुरू होती है, सभी जीवित जीवों की तरह समग्र सूक्ष्म जीव में भी माइक्रोबियल गतिविधियाएं कम हो जाती हैं। जाड़े के मौसम में बहुत अधिक तापमान गिरने से इस प्रक्रिया की दक्षता में बहुत कमी आ जाती है और अपघटन दर कम हो जाती है, इससे पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित होती है। इसके अलावा अधिक ठंडक के तापमान में रोग के रोगाणु भी पोषक तत्वों को पहुंचने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। नतीजतन, पौधों को मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

कैसे दूर होगी पीलेपन की समस्या?

अगर समस्या ज्यादा गंभीर दिख रही है तो 02 प्रतिशत यूरिया यानी (20 ग्राम यूरिया) प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अधिक ठंडक में गेहूं और अन्य फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए। खेतों के किनारे आदि पर धुंआं करें। इससे पाला का असर काफी कम होगा। पौधे का पत्ता झड़ रहा हो या पत्तियों पर धब्बा दिखाई दे तो डायथेन एम.45 नामक फफुंदनाशक की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से पाला का असर भी कम हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक किसानों को गेहूं की फसल पर यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए।

तीन खतरों से बचाएं गेहूं की फसल

इस समय ज्यादातर नम पूर्वा हवा चलती है जिससे फसल में रोग व कीट प्रकोप ज्यादा रहता है। पूर्वा हवा में फसल में नमी बनी रहती है और नमी की वजह से कई तरह के कीट और रोग के पनपने की आदर्श परिस्थियां बन जाती हैं।

हमारे किसान किसी भी कीट या रोग का प्रकोप होते ही सबसे पहले रासायनिक दवाओं की ओर भागते हैं जबकि वैज्ञानिक तरीके से कीट और रोग नियंत्रण में यह सबसे आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

कृषि मंत्रालय भारत सरकार के साल 2012.13 के आंकड़ों के मुताबिक देश के किसान प्रति 26 रुपए की फसल की रक्षा पर एक रुपए का रसायन खर्च करते हैं।

रोकथाम के तरीके

दीमक रोकथाम के लिए दूविवेरिया बसिअना दवाई या लिन्डेन दवा का सुरक्षित का छिड़काव करें। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप हो चुका है तो गोबर की खाद न डालेंए इसके अलावा दीमक प्रभावित क्षेत्र में नीम की खली 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं।

माहू

यह पौधे का रस चूसने वाले छोटे कीट होते हैं, इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़, पौधे की पत्तियों.बालियों से रस चूसते हैं। प्रबंधन के लिएनीम तेल 1500 पीपीएम दो मिली प्रति लीटर पानी में हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा इसकी रोकथाम के लिए येल्ले स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं या लाल मिर्च पाउडर के घोल का भी छिड़काव लाभकारी रहेगा।

गुलाबी तना बेधक

यह कीट तने को भीतर से खाकर उसे कमजोर कर देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फेरोमोने ट्रैप का प्रयोग करें और नेपियर या सुडान घांस को रक्षक फसल के रूप मे चारों तरफलगाएं।

झुलसा रोग

इस रोग में पत्तियों के नीचे कुछ पीले व कुछ भूरापन लिए हुए अण्डाकार धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे बाद में किनारों पर कत्थई भूरे रंग के हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए प्रोपिकोनोजोल 25 प्रतिशत ईसी रसायन के आधा लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

गेरुई या रतुआ रोग

इस रोग में फफूंदी के फफोले पत्तियों पर पड़ जाते हैं जो बाद में बिखर कर अन्य पत्तियों को ग्रसित कर देते हैं। इसके उपचार के लिए एक प्रोपीकोनेजोल 25 प्रतिशत ईसी रसायन की आधा लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

चूहे भी पहुंचाते हैं नुकसान

गेहूं की खड़ी फसल को चूहे बहुत अधिक नुकसान पहुचाते हैं,इस लिए फसल की अवधि में दो तीन बार इनकी रोकथाम की आवश्यकता रहती है। इसकी रोकथाम के लिए जिंक फास्फाइड या बेरियम कार्बोनेट से बने जहरीले चारे का प्रयोग करें। जहरीला चारा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड अथवा बेरियम कार्बोनेट100 ग्राम, गेहूं का आंटा 860 ग्राम, शक्कर 15 ग्राम तथा 25 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर बनाया हुआ जहरीला चारा प्रयोग करें।

संसाधनों पर बोझ बनती बढ़ती आबादी

विश्व और भारत का वनीय क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है वर्ष 1900 में जहां वनों का आवरण वैश्विक भूमि का 31.6 प्रतिशत था, वह वर्ष 2015 में केवल 30 प्रतिशत रह गया। इसके कारण जहां कार्बन सिंक में कमी आयी है। वहीं दूसरी तरफ वन्यजीवों के आवास का नुकसान भी हुआ है। वन और पेड़ों के आवरण कम होने से जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्राकृतिक जल के स्रोत कम होते जा रहे हैं, वह सात सात भूमि का जल स्तर पर गिरता जा रहा है। भूमि के उपजाऊपन में भी कमी आती जा रही है, हरियाणा में जिस तरह से फसल अवशेष जलने की समस्या बढ़ती जा रही है उसे एक तरफ जहां मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है उसके साथ साथ मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का भी नुकसान हो जाता है।

विश्व में वर्तमान में प्रति वर्ष 50 मिलियन टन ई .वेस्ट जनरेट होता और यह 2050 तक बढ़कर लगभग सौ मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगा। ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत से और चीन के बाद तीसरा सबसे अधिक ई .वेस्ट उत्पाद करने वाला देश है। ई .वेस्ट एक तरफ जहां ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है और वहीं दूसरी तरफ इससे हमारे जलीय स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं वह साथ साथ ये मानव और धरातल के अन्य जीवों पर भी

संपादकीय

नकारात्मक असर डालता है। इसके अतरिकत अकेले भारत में प्रतिवर्ष 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है।

प्रकृति को लेकर अब खुद से पेड़.पौधे लगाने चाहिए साथ ही साथ खुद के लगाये गए पेड़.पौधों को खुद ही संरक्षित करना चाहिए। पेड़ पौधों की कमी व बढ़ती जनसंख्या की वजह से जिस माह में जिस ऋतु को आना चाहिए। वह सही समय में नहीं आती, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मौसम चक्र बदल गया है इस बार गर्मी ने जो रंग दिखाया उससे वास्तव में सभी के चेहरे के रंग उड़ गए। सूर्य की तपिश में मानों हर जीव झुलस रहे हो। नदियों का पानी सूखने की कगार पर आ गया। यहां तक कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल सूख गए, पोखर, तलाब सूख गए। कुंआ का अस्तित्व तो विलुप्त ही है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कभी पानी की किल्लत होती ही नहीं थी। सूर्य की तपिश ऐसी की मानों जला ही दें और हुआ भी यही की हीटवेव के कारण कितनों की जानें चली गई। अधिकांश जगहों पर तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये सामान्य सी घटना नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? ये सोचने का विषय है। आने वाले 10 साल में स्थिति ऐसी ही रही तो ये कहना गलत नहीं होगा की आसमान से आग बरसेगी और ये सिलसिला बढ़ता ही रहा तो आने वाले 40.50 साल में पूरा देश पानी की समस्या से जूझ रहा होगा और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका होगा। तब की स्थिति की कल्पना ही भयभीत करती है। आने वाले समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। नदियां प्रदूषण मुक्त हो जाएगी ऐसी बातें करना ही मूर्खतापूर्ण है। हम भौतिक सुखों में प्रकृति को भूलते जा रहे है। पर्यावरण संरक्षण की बातें बस पर्यावरण दिवस पर ही सुनने को मिलती है। सच्चाई तो ये है कि हमारे पास इन विषयों पर सोचने के लिए समय ही नहीं है। कम से कम आने वाले वक्त के लिए तो अभी से कमर कस ही लेनी चाहिए कि अन्न .जल के अभाव में मरना है। अगर हम बच भी गए तो आने वाली पीढ़ी इसका दंश झेलेगी ही झेलेगी। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत रहा है। 2070 तक भारत की आधी आबादी सूर्य की तपिश और पानी के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहा होगाए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती आबादी की जरूरतों और सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जमीन से पानी निकाला जा रहा है। इससे पृथ्वी की धुरी प्रभावित हुई है। साथ ही इसके घूमने का संतुलन भी बिगड़ा है।

ज्योतिष दृष्टि से कैसा रहेगा नया साल 2024

(ज्योतिष) नए साल के जश्न को सभी तैयार हैं, हर कोई अपने तरीके से साल के स्वागत की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच कहीं न कहीं लोगों में आने वाला साल उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है इसको लेकर भी वे काफी उत्सुक हैं और ज्योतिष शास्त्र को खासा तवज्जो दे रहे हैं। अमजेर के ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन ने देश की कुंडली का अध्ययन किया और नव वर्ष भारत वर्ष के लिए क्या कुछ ला रहा है, कितना उतार.चढ़ाव होने वाला है इस पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। आईये जानते है कैसा रहेगा 2024

ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस बार नया वर्ष शुरू होने से पहले गजलक्ष्मी राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। 2024 का आगमन सोमवार को मघा नक्षत्र में हो रहा है। नव वर्ष पर सूर्योदय के समय चंद्रमा सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में मार्गी, बुध ग्रह वक्री तथा शनि कुंभ राशि में चलित रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष राजा मंगल एवं मंत्री शनि महाराज होंगे।

2024 में भारत में आपको अनेक उतार.चढ़ाव देखने को मिलेंगे। भारत की राजनीति में विशेष कानून व्यवस्था लागू होने के योग बन रहे हैं। विश्व के अनेक देश भारतवर्ष के साथ व्यापारिक संबंध बनाने को उत्सुक रहेंगे। पश्चिमी देशों में राजनीतिक संकट गहराएगा। भयानक विस्फोटक वातावरण से आंतरिक अशांति बनेगी। विश्व के प्रमुख देशों के मध्य युद्ध का भय बना रहेगा। विश्व के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों में परस्पर बैर भाव के कारण निरंतर युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अनेक देशों में प्राकृतिक प्रकोप से जन धन हानि होने की संभावना।

व्यापार के दृष्टिकोण से 2024 भारतवर्ष के लिए अत्यंत शुभ फल कारक रहेगा। भारत विश्व भर में व्यापार के माध्यम से नए आयाम स्थापित करेगा। विदेशनीति के कारण भारत विश्व विख्यात होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। आम जन मानस के लिए रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे तथा आय में बढ़ोतरी होगी। सभी व्यापारी वर्ग को वर्ष भर आय में उतार चढाव देखने को मिलेंगे।

मौसम के दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम फल कारक रहेगा। विश्व के अनेक स्थानों पर अग्निकांड एवं बम विस्फोटए आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग प्रचुरता से होता दिखाई देगा। आंधी, तूफान, खंडवृष्टि और भूकंप आदि प्रकोपों से आम जनमानस का जीवन अस्त.व्यस्त रहेगा। वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी। अन्नोत्पादन भी मध्यम रहेगा। विघ्न बाधा, विपत्ति दंगा फसाद, फसल को हानि पहुंचाने वाले उपद्रव/ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जीव.जंतुओं, पक्षियों आदि से फसल को हानि एवं राष्ट्र में तनाव की संभावना रहेगी। उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश आदि पर्वतीय राज्यों में अधिक वर्षा के कारण भूस्खलन, भूकंप आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2024 भारत वर्ष हेतु अनुकूल रहेगा

देश की सीमाओं पर अनेक प्रकार के उपद्रव आतंकवाद का भय बना रहेगा। भारत के शत्रु देशों द्वारा बनाई गई योजनाएं विफल होंगी। भारत की कूटनीति सफल रहेगी। महंगाई नियंत्रित करने में शासन विफल रहेगा। भारतीय राजनीति राष्ट्रवाद व धर्मनिरपेक्षवाद की दो धाराओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीतिक पार्टियां सत्तासीन होंगी। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्वास्थ्य के परिपेक्ष से वर्ष 2024 सामान्य फल कारक रहेगा। अनेक गंभीर बीमारियों का भय बना रहेगा। बाल्यावस्था के जातकों को गंभीर बीमारी का भय वर्ष के उत्तरार्द्ध में बना रहेगा जैस शीत/ ठंड, ज्वरादि गंभीर रोग व किसी स्पर्शजनित रोग का प्रकोप हो सकता है। कोरोना महामारी का प्रभाव शिशुओं एवं किशोरावस्था के जातकों में अधिक देखने को मिलेगा अतः सावधानी बरतें। सामाजिक नियमों का पालन करें।

करियर

साल 2024 का कुल अंक 8 है। आसान शब्दों में कहें तो 2024 यूनिवर्सल ईयर 8 है। यूनिवर्सल ईयर 8 ऊर्जा का सूचक है। इसे पावर नंबर भी कहा जाता है। यह अंक ऊर्जा का भी सूचक होता है। अतः साल 2024 सभी मामलों में बेहद शुभ रहने वाला है।कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। वर्ष के आरंभ से अप्रैल तक सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आप व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। नवीन व्यापार शुरू करने के लिए अच्छा समय है। राशि में स्थित गुरु नवीन विचारधारा और नई योजनाओं को जन्म देगा, जिससे अपने व्यापार को और मजबूत बना सकते हैं। द्वादश भाव में भाव में स्थित राहु के प्रभाव से कार्यों में गुप्त शत्रुओं द्वारा रूकावटों को आप अपने विवेक से अनुकूल बना लेंगे। द्वादश भाव का राहु व्यावसायिक यात्राएं भी देगा यदि आप विदेश जाने की चाह रखते हैं, तो इस वर्ष में इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए छठें भाव का केतु स्थांतरण के योग बना सकता है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में साल 2024 अच्छा ही रहने वाला है।

परीक्षा प्रतियोगिता

यह वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। यदि उच्च शिक्षा हेतु उच्च शैक्षिक संस्थान में प्रवेश पाना चाहते हैं तो वर्ष का प्रारंभ अनुकूल है। पंचम स्थान में गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा।

15 जनवरी को मनेगा सूर्य आराधना का पर्व मकर संक्रांति, वरियान सहित बन रहे कई अद्भूत संयोग

(ज्योतिष)। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति पर कई विशेष शुभ संयोग बन रहेहै।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी) अजमेर के अनुसार सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति तिथि पर गंगा स्नान कर विधि.विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते है।मकर संक्रांति तिथि पर रवि योग समेत कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस दिन पुण्य काल सुबह काल 07 बजकर 15 मिनट से लेकर संध्याकाल 05 बजकर 46 मिनट तक है। वहींए महा पुण्य काल सुबह 07 बजकर 15 मिनट से लेकर 09 बजे तक है। इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है।

वरीयान योग

मकर संक्रांति तिथि पर वरीयान योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण देर रात 11 बजकर 11 मिनट तक है। ज्योतिष वरीयान योग को शुभ योग मानते हैं। इस योग में शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन खरमास समाप्त हो जाएगा।

रवि योग

ज्योतिषियों की मानें तो मकर संक्रांति पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 7 बजकर 15 मिनट से लेकर 08 बजकर 07 मिनट है। इस योग में पूजा.पाठ और दान.पुण्य करने से आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है।

करण

मकर संक्रांति तिथि पर बव और बालव करण का निर्माण हो रहा है। बव करण का निर्माण दोपहर 3 बजकर 35 मिनट तक है। इसके पश्चात, बालव करण का योग है।। ज्योतिष बव और बालव दोनों करण को शुभ मानते हैं। इन योग में शुभ कार्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन देवों के देव महादेव, जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के साथ संध्याकाल 07 बजकर 45 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान साधक भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। धार्मिक मत है कि मां गौरी के साथ भगवान शिव के रहने के समय रुद्राभिषेक करने से साधक के घर में सुख और समृद्धि आती है।

पर्व एक नाम अनेक

ज्योतिषाचार्य जैन के अनुसार मकर संक्रान्ति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है।यह पर्व भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के चौदहवें या पन्द्रहवें दिन ही पड़ता है, इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता हैं जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रान्ति पर्व को कहीं.कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण इस पर्व को उतरायण सूर्य उत्तर की ओर भी कहते है। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है। और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।

ऐतिहासिक मान्यता

ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है, अतः इस दिन को मकर संक्रान्ति के नाम से जाना जाता है। । इस दिन ही गंगाजी भगीरथ के पीछे.पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं। मान्यता है कि चिरकाल में राजा भागीरथ ने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने हेतु मां गंगा की कठिन तपस्या की थी। मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के पश्चात राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अतः संक्रांति तिथि पर पूर्वजों का तर्पण एवं पिंडदान भी किया जाता है।

कैसे आगे बढ़ेगी खेती - किसानी? कृषि विज्ञान केंद्रों में खाली हैं 3499 पद!

हलधर किसान 88174 02860

देश के किसानों को जागरूक करके खेती.किसानी के विकास में अहम योगदान देने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाने में भले ही केंद्र सरकार जोर दे रही है। पिछले एक साल में पांच नए सेंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि इनमें 31.56 फीसदी पद खाली हैं। यही समस्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भी है, जहां वैज्ञानिकों के 21 और तकनीकी कर्मियों के 34 फीसदी पद खाली हैं। जबकि आईसीएआर कृषि क्षेत्र में शोध करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था है।

देशभर में 638 कृषि विज्ञान केंद्रोंमें अलग.अलग स्तरों पर कुल 3,499 पद खाली हैं, जिससे इन केंद्रों के प्रभावी कामकाज पर असर पड़ रहा है। उत्तरी राज्यों में, जम्मू और कश्मीर के 19 केवीके में 172 पद खाली हैं, इसके बाद हरियाणा के 18 केवीके में 91 रिक्त पद खाली हैं, पंजाब के 22 केवीके में 74 रिक्त पद हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 12 केवीके में 26 पद खाली पड़े हैं। केवीके में खाली पड़े पदों ने इन केंद्रों के ऑपरेशन क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जो किसानों तक कृषि ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

केवीके वाले जिलों की कुल संख्या 638

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि देश में केवीके वाले जिलों की कुल संख्या 638 है। यहां तक कि कृषि पर राष्ट्रीय आयोग ने अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार पर अपनी रिपोर्ट में प्रत्येक जिले में एक केवीके रखने की सिफारिश की गई है, जबकि हाल ही में बनाए गए जिलों में नए केवीके की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है, वर्तमान खाली पद को भरना एक चुनौती पेश करती है।

यूपी में रिक्त पदों की संख्या सबसे अधिक

आंकड़ों से पता चला कि उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों की संख्या सबसे अधिक है, केवीके में 437 पद भरे जाने की प्रतीक्षा में हैं। इसके बाद राजस्थान (351), मध्य प्रदेश (350), बिहार (230) और झारखंड (206) हैं। इन राज्यों में रिक्तियों की चिंताजनक संख्या इन महत्वपूर्ण कृषि संस्थानों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और इन पदों को भरने के लिए काम शुरू करने की बात चल रही है।

भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से चलाए जाने वाली कृषि विज्ञान केंद्र योजना, राज्य सरकारों, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयोंए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर.सरकारी संगठनों और स्वयं आईसीएआर सहित विभिन्न मेजबान संगठनों के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होती है। मंत्री के अनुसार इन रिक्तियों को भरने की जिम्मेदारी संबंधित मेजबान संगठनों की है और आईसीएआर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

कृषि क्षेत्र में विकास की गिरावट चिंताजनक

खेती.किसानी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा जलवायु परिवर्तन

हलधर किसान। कृषि क्षेत्र की धीमी रफ्तार के चलते न सिर्फविकास दर सुस्त पड़ी है बल्कि यह किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य की राह में बाधा बन सकती है।

खराब मौसम के कारण खरीफउत्पादन में गिरावट के कारण जुलाई.सितंबर तिमाही में देश के कृषि क्षेत्र की विकास दर घटकर मात्र 1.2 प्रतिशत रह गई। इसका प्रतिकूल प्रभाव चालू रबी सीजन पर पड़ा है और सामान्य से कम मानसून के कारण कुल बोए गए क्षेत्र में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। मिट्टी में नमी की कमी हो गई है और जलाशयों में पानी का भंडारण कम हो गया है। गेहूं और दालों के रकबे में क्रमशः 3 और 8 प्रतिशत की गिरावट आई है, इससे आगे चलकर खाद्य उत्पादन में गिरावट को लेकर चिंता बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन की इस जटिल घटना से निपटने के लिए गतिशील प्रतिक्रिया रणनीतियों को विकसित करने के लिए नीति निर्माताओं और वैज्ञानिक समुदाय के भीतर अब एक बड़ी चिंता है, खासकर कुछ राज्यों में विशाल क्षेत्र अभी भी वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि, रबी के रकबे में मौजूदा गिरावट के बावजूद, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में अंतर को संभावित रूप से कम किया जा सकता है। उनका अनुमान है कि रबी फसलों के लिए कुल बोया गया क्षेत्र, पिछले पांच वर्षों के औसत स्तर (648 लाख हेक्टेयर) तक पहुंच सकता है। अधिकारी दलहन के रकबे में कमी का कारण धान जैसी खरीफ फसलों की देर से कटाई और फसल विविधीकरण की प्रवृत्ति को मानते हैं। इसमें कुछ राहत की बात है कि सरसों और रेपसीड सहित तिलहनों का रकबा इस साल 2022 की तुलना में 1 लाख हेक्टेयर अधिक है, इससे देश के खाद्य तेलों के आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी।

वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि तिलहन पर जोर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के रणनीतिक उपायों को दर्शाता है, जबकि मौसम संबंधी बाधाओं के कारण चुनौतियां बनी रहती हैं। कृषि मंत्रालय का संभावित पलटाव का पॉजिटिव आउटलुक कृषि क्षेत्र की लचीलापन पर आधारित है। आगामी सीजन में मजबूत खाद्यान्न उत्पादन हासिल करने के लिए फसल विविधीकरण को संतुलित करना और नमी की कमी को दूर करना महत्वपूर्ण होगा। इस वर्ष की शुरुआत में लोकसभा में पूर्व कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, 2014 के बाद से फसलों के लिए बीजों की 1, 888 जलवायु अनुकूल किस्में विकसित की गई हैं। इसके अलावा, सूखे, बाढ़, ठंढ और गर्मी की लहर जैसी चरम मौसम की स्थिति वाले जिलों और क्षेत्रों में कृषक समुदायों के बीच व्यापक रूप से अपनाने के लिए 68 स्थान विशिष्ट जलवायु लचीली प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया गया है।

भारत के कृषि निर्यात में 4.5 अरब डॉलर गिरावट की उम्मीद

भारत दुनिया में गेहूं, चावल और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन बढ़ती घरेलू कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इन वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर किया गया है। देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इसलिए, निर्यात पर प्रतिबंध से इन देशों में भोजन की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है। इस साल भारत के कृषि निर्यात में 4 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर की गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल का मानना है कि अन्य कृषि वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी से इस साल निर्यात घाटा पूरा हो जाएगा। अग्रवाल ने कहा, अगर हम गेहूं और चावल जैसी कृषि वस्तुओं को हटा दें, जिनका निर्यात निर्यंत्रित है, तो अन्य खाद्य निर्यात 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ रहा है। इसलिए चीनी, गेहूं और चावल पर प्रतिबंध के कारण लगभग 4 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर की कमी के बावजूद, हमें पिछले साल के निर्यात स्तर को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल अप्रैल और नवंबर के बीच मांस और डेयरी, अनाज की तैयारी और फलों और सब्जियों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर, रेटिंग एजेंसी आईसीआर की एक रिपोर्ट के अनुसारए खरीफ उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान से पता चलता है कि खाद्यान्न उत्पादन घटकर चार साल के निचले स्तर 148.6 मिलियन टन पर आ गया है, जो पिछले साल के अंतिम अनुमान से 4.6 प्रतिशत कम है। यहां तक कि जिन फसलों के बोए गए क्षेत्र में इस वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उनके उत्पादन में गिरावट देखने की उम्मीद है, इसमें गन्ना (-11.4:) चावल (-3.8) और मोटे अनाज (-6.5) शामिल है। आईसीआर, की रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश फसलों के उत्पादन में गिरावट उनके बोए गए क्षेत्र में गिरावट से बड़ी है, जो पैदावार में संकुचन को दर्शाती है।

बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान

जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश भी हुई है इससे फसलों को नुकसान हुआ है। इस वर्ष राज्यों में लगभग 8.68 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ या भारी वर्षा से प्रभावित होने की सूचना है। जून में मानसून ; देरी से शुरू हुआ था, इसके बाद जुलाई में अधिक बारिश हुई, उसके बाद अगस्त में कमी हुई और फिर सितंबर में पंजाब और हरियाणा जैसे देश के कुछ हिस्सों में फिर से अधिक बारिश हुई, इससे खड़ी फसल पर असर पड़ा। भारत की लगभग 80 प्रतिशत वर्षा दक्षिण.पश्चिम मानसून के दौरान होती है, इससे देश के जलाशय भी भर जाते हैं, जिनका उपयोग अगले कृषि मौसम के दौरान सिंचाई के लिए किया जाता है। इस वर्ष कम वर्षा के कारण, जलाशय में पानी का भंडारण पिछले वर्ष का लगभग 75 प्रतिशत बेमौसम बारिश भी होने की सूचना है, जो आगामी रबी सीजन में कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।

दिसंबर 2023 में 10.75 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 92.87 मिलियन टन तक पहुंचा

हलधर किसान (दिल्ली)। एक ओर जहां पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को थामने के लिए कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर भारत में कोयला उत्पादन बढ़ता जा रहा है।

कोयला उत्पादन पिछले वर्ष के 83.86 मिलियन (8.38 करोड़) टन के आंकड़े को पार करते हुए 92.87 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया है और यह 10.75 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

केंद्र सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन दिसंबर 2023 में 8.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 71.86 मिलियन टन हो गया है, जबकि दिसंबर 2022 में यह 66.37 मिलियन टन था।

संचयी कोयला उत्पादन (दिसंबर 2023 तक) वित्तीय वर्ष 23.24 में बढ़कर 684.31 मिलियन टन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 22.23 की समान अवधि के दौरान यह 608.34 मिलियन टन था। यह उत्पादन में 12.47 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

दिसंबर 2023 में कोयला प्रेषण 86.23 मिलियन टन तक पहुंच गयाए जो दिसंबर 2022 में 79.58 मिलियन टन था। यह वृद्धि दर 8.36 प्रतिशत रही।

कोल इंडिया लिमिटेड का प्रेषण दिसंबर 2023 में 66.10 मिलियन टन रहा, जबकि दिसंबर 2022 में 62.66 मिलियन टन था और यह 5.49 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 23.24 में संचयी कोयला प्रेषण दिसंबर 2023 तक 11.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 709.80 मिलियन टन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 22.23 की इसी अवधि के दौरान यह 637.40 मिलियन टन था। सरकार का कहना है कि पिछले सालों में कोयला क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक का स्तर उल्लेखनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इस वृद्धि में कोयला सार्वजनिक उपक्रमों ने योगदान दिया है और इस प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

साल 2024 में दुनिया को और अधिक युद्ध या अशांति देखने को मिलेगी?

88174 02860
हलधर किसान (वैश्विक)।

अफसोस की बात है कि 2022 में रुस- यूक्रेन के बाद अब 2023 भी वैश्विक मंच पर एक हिंसक वर्ष रहा है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे हजारों फलस्तीनियों और सैकड़ों इजरायलियों की मौत हो गई, जिनमें दोनो तरफ्के बहुत से बच्चे शामिल हैं। और रूस तथा यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी रहा जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा।

इन दो संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप, अन्य देश कई लोगों के लिए रडार से बाहर हो गए हैं। हालांकि, इनमें से कुछ देश बढ़ती अशांति से निपट रहे हैं, जो 2024 में भड़क सकती है और वैश्विक सुर्खियों में आ सकती है। तो, आने वाले वर्ष में हमें कहां नजर रखनी चाहिए? यहां पांच स्थान बताए गए हैं जहां मेरा मानना है कि नागरिक संघर्ष या अशांति बदतर हो सकती है और संभावित रूप से हिंसा हो सकती है।

म्यांमार 2021 में अराजकता की स्थिति में आ गया जब एक सैन्य तख्तापलट ने आंग सान सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और व्यापक नागरिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जो अंततः सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया। 135 जातीय समूहों के घर इस देश में शायद ही कभी शांति रही हो। तख्तापलट से पहले वर्षों तक, सेना और कई अल्पसंख्यक जातीय समूहों के बीच नागरिक संघर्ष चल रहा था, जो लंबे समय से अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और राज्य से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तख्तापलट के बाद यह विस्फोट हुआ क्योंकि जातीय मिलिशिया समूह जुंटा का विरोध करने वाले बामर बहुमत के लोकतंत्र समर्थक सेनानियों के साथ सेना में शामिल हो गए।

साल 2023 के अंत में एक समन्वित उत्तरी आक्रमण के साथ उनका प्रतिरोध बढ़ गया, जिससे सेना को कई वर्षों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। विद्रोहियों ने चीन के साथ उत्तरपूर्वी सीमा पर कस्बों और गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसमें प्रमुख व्यापार मार्गों पर नियंत्रण भी शामिल था। इससे पश्चिमी राखीन राज्य के साथ.साथ अन्य क्षेत्रों में भी नए सिरे से लड़ाई शुरू हो गई। इन अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिरोध की दृढ़ता, सेना के समझौता करने से इनकार के साथ मिलकर, यह सुझाव देती है कि 2024 में देश का गृह युद्ध काफी खराब हो सकता है और इसे अंतरराष्ट्रीय ध्यान फिर से हासिल हो सकता है।

माली अफ्रीका के अशांत साहेल क्षेत्र के देश माली में 2023 के दौरान तनाव बढ़ता गया और अब पूर्ण पैमाने पर गृहयुद्ध छिड़ने का खतरा है। माली लंबे समय से विद्रोही गतिविधियों से जूझ रहा है। 2012 में, माली की सरकार तख्तापलट में गिर गई और इस्लामी आतंकवादियों द्वारा समर्थित तुआरेग विद्रोहियों ने उत्तर में सत्ता पर कब्जा कर लिया। माली में स्थिरता लाने के लिए 2013 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्थापना की गई थी। फिर, 2015 में, प्रमुख विद्रोही समूहों ने माली सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2020 और 2021 में दो और तख्तापलट के बाद, सैन्य अधिकारियों ने अपनी शक्ति मजबूत की और कहा कि वे पूरे माली पर राज्य का पूर्ण क्षेत्रीय नियंत्रण बहाल करेंगे।

शासन ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को देश से वापस जाने पर जोर दिया, जो उसने जून 2023 में किया। इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों के भविष्य में उपयोग को लेकर सेना और विद्रोही बलों के बीच हिंसा भड़क उठी। नवंबर में, कथित तौर पर रूस के वैगनर समूह द्वारा समर्थित सेना ने रणनीतिक उत्तरी शहर किडाल पर नियंत्रण कर लिया, जिस पर 2012 से तुआरेग बलों का कब्जा था। यह 2015 से चली आ रही नाजुक शांति को कमजोर करता है। इसकी संभावना नहीं है कि सेना उत्तर में विद्रोहियों के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेगी। साथ ही उग्रवादियों के हौंसले बुलंद हैं। 2015 का शांति समझौता अब लगभग खत्म हो चुका है, हम 2024 में अस्थिरता बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं।

लेबनान 2019 में, लेबनान में उन नेताओं के खिलाफ व्यापक नागरिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गयाए जिनके बारे में माना जाता था कि वे आबादी की दिन.प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। सरकार में फेरबदल, बढ़ते आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर बंदरगाह विस्फोट से भ्रष्ट आचरण उजागर होने से स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक सुधार की कमी के लिए सितंबर में लेबनान की आलोचना की। लेबनानी सरकार राष्ट्रपति की नियुक्ति पर भी सहमति बनाने में विफल रही है, यह पद एक वर्ष से अधिक समय से खाली है। इससे लेबनान में नाजुक सत्ता.साझाकरण व्यवस्था के कमजोर होने का खतरा है, जिसमें प्रधान मंत्री, स्पीकर और राष्ट्रपति के प्रमुख राजनीतिक पद क्रमशः सुन्नी.मुस्लिम, शिया.मुस्लिम और ईसाई मैरोनाइट को आवंटित किए जाते हैं। हाल ही में, इज़राइल और हमास के बीच युद्ध के लेबनान तक फैलने की आशंका जताई गई है, जो हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह का घर है, जो 100,000 लड़ाकों की सेना होने का दावा करता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह लेबनान की आर्थिक सुधार की प्रमुख आशा के रूप में पर्यटन को खतरे में डालता है। ये कारक 2024 में अधिक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक पतन का कारण बन सकते हैं।

पाकिस्तान: 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से, सेना ने राजनीति में हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाई है। हालांकि पाकिस्तानी नेता लोकप्रिय रूप से चुने जाते हैं, सैन्य अधिकारियों ने कई बार उन्हें सत्ता से हटा दिया है। 2022 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पाकिस्तान के उग्रवादी नेताओं से मोहभंग हो गया। बाद में उन्हें संसद के मतदान में सत्ता से बेदखल कर दिया गया और बाद में उन आरोपों पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके बारे में उनके समर्थकों का दावा है कि ये राजनीति से प्रेरित हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. सेना के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन जो एक समय अकल्पनीय था। पाकिस्तान को पड़ोसी अफगानिस्तान में अस्थिरता और बढ़ते आतंकवादी हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। संघर्षरत अर्थव्यवस्था और 2022 की विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान के कारण ये सुरक्षा चुनौतियां और भी जटिल हो गई हैं। पाकिस्तान में फरवरी 2024 में संसदीय चुनाव होने की उम्मीद है, जिसके बाद वर्तमान सैन्य कार्यवाहक सरकार द्वारा नागरिक शासन को सत्ता हस्तांतरित करने की उम्मीद है। कई लोग सेना पर करीब से नजर रख रहे हैं। यदि सत्ता का यह हस्तांतरण नहीं होता है, या देरी होती है, तो नागरिक अशांति हो सकती है।

श्रीलंका: श्रीलंका को 2022 में एक विकट आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिसके कारण ईंधन, भोजन और दवाओं की गंभीर कमी हो गई। नागरिक विरोध के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से भागना पड़ा। उनकी जगह वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंह ने ले ली। 2023 में स्थिरता लौट आई क्योंकि श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बेलआउट समझौते के हिस्से के रूप में आर्थिक सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया। हालाँकि, राजनीतिक अभिजात वर्ग और देश की आर्थिक कठिनाई के अंतर्निहित चालकों के प्रति व्यापक असंतोष को कम करने का उपाय नहीं किया गया है। 2024 के अंत तक श्रीलंका में भी चुनाव होने हैं। मौजूदा राष्ट्रपति विक्रमसिंह के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी भाग्य आजमाने की संभावना है, लेकिन जनता के बीच उनका भरोसा कम है। उन्हें भ्रष्ट राजनीतिक अभिजात वर्ग के करीबी के रूप में देखा जाता है। यह असंतोष नए सिरे से विरोध प्रदर्शन का कारण बन सकता है . खासकर अगर अर्थव्यवस्था फिर से लड़खड़ाती है . उसी स्थिति की पुनरावृत्ति, जिसके कारण 2022 में राजपक्षे को सत्ता से बाहर होना पड़ा था।

तकनिकः बिना मिट्टी-पानी के हो रही खेती, इजरायली तकनीक से किसान ने किया कमाल

हलधर किसान (राजस्थान)।
88174 02860

अब तक हम और आप यही सुनते और देखते आए हैं कि बिना मिट्टी.पानी के खेती संभव नहीं है। बिना मिट्टी के पेड़.पौधे कहां लगाएंगे जाएंगे? अगर आपके मन में भी इसी तरह से सवाल हैं तो बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा में बिना मिट्टी.पानी के खेती हो रही है। भीलवाड़ा, जिसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं, वहां अब इजरायली तरीके से खेती की जा रही है।

बिना मिट्टी.पानी के खेती राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खेती का नया तरीका अपनाया जा रहा है। यहां किसान खेती के नए तरीकों पर काम कर रहे है। इस तकनीक से वो 30 से ज्यादा तरह की सब्जियां और फल उगा रहे हैं। इन फलो.सब्जियों की देश.विदेश में खूब डिमांड बढ़ रही है। भीलवाड़ा के अलावा इन फलों और सब्जियों को दिल्ली, गुजरात ए मुंबई जैसे महानगरों में बेचा जा रहा है। इस खास तकनीक की वजह से किसान ऑफ सीजन में भी सभी तरह की सब्जियां उगा लेते हैं।

क्या है इजरायली तकनिक?

इजरायली तरीके से की जा रही खेती में मिट्टी.पानी के बजाए फसल को ऑक्सीजन की मदद से उगाया जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले एक एग्रीकल्चर फार्म में स्टैंड बनाया जाता है। इसे इस तरह से तैयार किया जाता है, ताकि उससे लगातार पानी बहता रहे और पौधों को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियल, मैग्नीशियल, सल्फर और आयरन जैसे पोषक तत्व मिलते रहे। इस तकनीक में 80 फीसदी पानी की बचत हो जाती। इस तकनीक में किसानों को इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि जहां पौधे लगाए गए हैं, वहां का तापमान 15 से 32 डिग्री रहे। मिट्टी के बजाए नारियल के भूसे से बने कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाता है। खेती के इस उन्नत तकनीक में नए प्रयोग जारी है। इस तकनीक में कम जगह, बिना मिट्टी और कम पानी में फसलों को उगाया जाता है। भीलवाड़ा के किसान टमाटर, स्ट्रॉबेरी, खीरा जैसे फसलों की खेती कर रहे हैं। संगम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. करुणेश सक्सेना ने बताया कि हमने एग्रीकल्चर फार्म में एक नवाचार किया है, जिसमें मिट्टी की जगह नारियल के भूसे से बनाए कोकोपिट का उपयोग किया जाता है। हम इस तकनीक के माध्यम से छात्रों को शिक्षित भी कर रहे हैं, जिससे भविष्य में उन्नत खेती की जा सके।

वैज्ञानिकों की बनाई खास मिट्टी में पैदावार होगी दोगुनी

वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी का नाम दिया

(अंतर्राष्ट्रीय)। कहते है आवश्यकता अविष्कार की जननी होती है, ऐसे ही खाद्य जरूरतों की पूर्ति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीडन के वैज्ञानिकों ने विद्युत सुचालक एक ऐसी मिट्टी विकसित की है जिससे औसतन 15 दिन में जौ के पौधों की 50 प्रतिशत अधिक वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है। मिट्टी रहित खेती की इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स के रूप में जाना जाता है। इस विधि में ऐसी जड़ प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जिसे खेती के नए सब्सट्रेट (ऐसा पदार्थ या सतह जिस पर कोई पौधा बढ़ता है) के माध्यम से विद्युत रूप से उत्तेजित किया जाता है।

स्वीडन स्थित लिंकोपिंग विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एलेनी स्तावरिनिडो ने कहा दुनिया की आबादी बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है इसलिए यह स्पष्ट है कि हम खेती के केवल पहले से मौजूद तरीकों से पृथ्वी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम शहरों में भी बहुत नियंत्रित परिवेश में फसल उगा सकते हैं। टीम ने हाइड्रोपोनिक खेती के अनुरूप एक विद्युत सुचालक खेती सब्सट्रेट विकसित कियाए जिसे वे ई.सॉइल कहते हैं।

प्रोसीडिंग्स ऑफद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि विद्युत सुचालक मिट्टी में उगाए गए जौ के पौधे 15 दिनों में तब 50 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़े जब उनकी जड़ों को विद्युतीय रूप से उत्तेजित किया गया। हाइड्रोपोनिक खेती का मतलब है कि पौधे मिट्टी के बिना उगते हैं, उन्हें केवल पानी, पोषक तत्वों और ऐसे सब्सट्रेट की आवश्यकता होती है जिससे उनकी जड़ें जुड़ सकें।

इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी क्या है?

लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर एलेनी स्टावरिनिडों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी का इस्तेमाल जौ के पौधों पर किया, प्रयोग के नतीजे चौंकाने वाले थे। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी क्या है? लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने मिट्टी को कुछ इस तरह से तैयार किया है, जो सामान्य मिट्टी से कहीं ज्यादा उपजाऊ है? इस मिट्टी में पौधों के बढ़ने की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। दरअसल, वैज्ञानिकों ने मिट्टी को कुछ ऐसे तैयार किया है, जिससे बिजली प्रवाहित करके खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी नाम दिया है।

मिट्टी की नही होगी दरकार

शोधकर्ताओं के मुताबिक, दुनियाभर के देशों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमों में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त फसल उगाना आसान नहीं है। ये तय है कि पारंपरिक तरीकों से खेती करके बढ़ने वाली आबादी का पेट नहीं भरा ता सकता है। उनका दावा है कि ई.सॉइल के जरिये पैदावार बढ़ाकर भविष्य के खाद्य संकट से निपटा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी का प्रयोग जौ के पौधे पर किया। इसमें पौधे की जड़ पर बिजली का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके का प्रयोग पानी में पौधों को उगाने की विधि हाइड्रोपोनिक्स पर किया गया। बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स विधि में पौधों को उगाने के लिए जहां मिट्टी की दरकार नहीं होती, वहीं पानी की भी बहुत कम जरूरत होती है।

कैसे बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी?

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस विधि का इस्तेमाल कर जौ, हर्ब और कुछ सब्जियों को उगाने में सफलता मिली है। इस तरीके से उगाई जाने वाली जौ की फसल की बढ़त पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के जरिये अच्छा असर डाला जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी को एक तरह के बायोपॉलिमर सेल्युलोज से बनाया गया है। इसमें पीडॉट नाक का प्रवाहकीय पॉलिमर मिलाया गया, फिर इसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन गुजारा गया। यह मिट्टी बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करती है। यही नहीं, इससे हाई वोल्टेज का खतरा भी नहीं होता है। नए शोध ने हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। शोध में पाई गई विधि के जरिये उन इलाकों में फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जहां मौसम अक्सर खराब रहता है या जहां की मिट्टी फसल के लायक नहीं है। लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रयोगशाला में एसोसिएट प्रोफेसर एलेनी ने हाइड्रोपोनिक खेती के लिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव कल्टीवेशन सब्सट्रेट विकसित किया है। इसे ही वह इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी कहती हैं। लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के मुताबिक, यह संयोजन नया नहीं है, लेकिन खेती में इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया है।

नवंबर माह के अंक की प्रश्नोत्तरी के विजेता को पुरस्कृत करते संस्था के मार्गदर्शक एवं संरक्षक श्री विनोद जैन

सतना को व्हाइट टाइगर सफारी के बाद अब मिलेगी काऊ सफारी की भी पहचान!

उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा बगदरा घाटी में बनेगा गौ अभ्यारण्य

हलधर किसान (मप्र- वन)। व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला सतना जिला अब एक बार फिर चर्चाओं में है। यहां व्हाइट टाइगर सफारी के साथ अब काऊ सफारी की योजना भी बनाई जा रही है। इसका खुलासा खुद नई सरकार के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया है।

डिप्टी सीएम शुक्ल बगदरा में गौ.अभयारण्य के विकास की योजना की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने बताया काऊ सफारी की योजना मझगंवा के जंगल में बगदरा घाटी गोचर के लिए उत्तम जगह हो सकती है। वहां भारी संख्या में गौ वंश का समूह होता है और वहां 10, 000 गो वंशों को संरक्षण मिल सकता है। इससे न केवल गौ वंश सुरक्षित होगा, बल्कि वहां के किसानों की फसलों को भी सुरक्षा मिलेगी। इसलिए काऊ सफारी के रूप में जल्द ही गौ.अभयारण्य की स्थापना की जा सकती है।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने घोषणा की है कि चित्रकूट के बगदरा घाटी में गौ अभयारण्य की स्थापना की जाएगी, जो गौवंश के संरक्षण के लिए होगा। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र दिनों से गौमाता के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता रहा है। उन्होंने बताया कि बगदरा घाटी में सड़कों के दोनों ओर 20.20 हेक्टेयर क्षेत्र में वन्य जीवन क्षेत्र को फेंसिंग के जरिए सुरक्षित किया जाएगा। यहां पर लगभग 50 एकड़ जमीन पर गौशाला और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बसामन मामा गौ अभयारण्य की तर्ज पर यहां भी दानदाताओं और जनसहयोग से गौशाला के संचालन में सहयोग लिया जाएगा। गौवंश के सरंक्षण के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 हजार गौमाता के संरक्षण के लिए गौ.अभयारण्य विकसित किए जाने के प्रयास होने चाहिए।

प्रभारी कलेक्टर डॉ. परीक्षित झाड़े और जिला वनमंडलाधिकारी विपिन पटेल ने बगदरा घाटी में गौ अभ्यारण्य की सीमाएं और कार्य योजना प्रस्तुत की। यहां पर लगभग बीस हजार गौवंशीय पशुओं को संरक्षण देने की योजना है। इसके अलावा, बगदरा घाटी के पास स्थित ग्राम पिण्डरा और पड़मनिया जागीर में गौशालाएं चलाई जा रही हैं। सतना में स्वीकृत कुल 110 गौशालाओं में से 90 गौशालायें पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं। बैठक में गौशालाओं के संचालन से स्थानीय जनों की आजीविका सुधार में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी गई। बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधि राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी.कर्मचारी उपस्थित थे।

परखें कृषि ज्ञान, आसान सवालों का जवाब देकर पाएं आकर्षण उपहार

हलधर किसान से जुड़े पाठको के लिए हम लाए कृषि से जुड़े आसान सवाल, जिनके जवाब देकर आप अपना सामान्य ज्ञान परखने के साथ ही पा सकते है आकर्षक उपहार,

तो इस अंक में कृषि कीट विज्ञान एवं खरपतवारनाशी प्रश्नोत्तरी है-

प्रश्न. धान के गंधी कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानिकारण होती है?

अ - प्रौढ़
ब - लार्वा
स - प्यूपा
द - प्रौढ+ निम्फ

आपका जवाब .....

प्रश्नः- आम का मीलीबग कहां अंडे देता है?

अ- पत्तियों पर
ब- भूमि के अंदर
स- छिलके की दरारों पर
द- इनमें से कोई नही

आपका जवाब.......

प्रश्नः- इनमें से कौन सा कीट नही है?

अ- घरेलू मक्खी
ब- दीपक
स- मकड़ी
द- खटमल

आपका जवाब .....

प्रश्नः- मधुमक्खियों की भाषा बांचने के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन थे?

अ- सीवी रमण
ब- एडिसन
स- आरएल पेटन
द- वाने फ्रिश कार्ल

आपका जवाब........

दिसंबर माह के सवालो का सही जवाब, सवाल 1-ब, सवाल 2 -अ, सवाल 3-स, सवाल 4 का उत्तर- ब है।

नोटः आपके जवाब हमें इस प्रश्नोत्तरी में दर्ज कर अखबार की कटिंग 25 नवंबर तक हमारे वाट्सएप्प नंबर (88174 02860) पर, या हमारे मुख्य कार्यालयः हमारे प्रधान कार्यालय 598, विगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है। पर डाक के जरिये भेज सकते है। सही जवाब देने वाले पाठको का लॉटरी के जरिये परिणाम निकाला जाएगा। सही जवाब देने वाले विजेता को हलधर किसान की ओर से आकर्षण उपहार उनके भेजे गए पते पर भेजे जाएंगे। अगले अंक में हम सही जवाब और विजेता का नाम घोषित करेंगे।

ई- मेल - (haldharkisankgn@gmail.com) पर भी भेज सकते है।

खेती.किसानी के लिए कैसा गुजरा साल, क्यों ख़ास है 2024?

(खेती.किसानी)। साल का आख़िरी महीना दिसंबर आते ही लोगों के मन में बीते साल अपने जीवन में घटित तमाम तरह की घटनाओं की यादें जरूर ताजा हो जाती हैं। बीते साल जीवन में हासिल होने वाली उपलब्धियां और मिलने वाली कई तरह की नाकामियां दोनों ही जेहन में जरूर रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ आने वाले नए साल को लेकर लोगों के मन में तरह.तरह के सवाल, उत्सुकता, उमंग और नई आशाएं भी आती हैं। बितता साल 2023 कई यादे छोड़कर जाने वाला है। इस साल ने कभी हसाया.कभी रुलाया। सारी यादों को अपने साथ लिए रविवार को 2023 का सूर्य अस्ताचंल हो गया और सोमवार को नए सपनो व उम्मीदों के साथ सूर्योदय हुआ।

बीता साल खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए मिला जुला रहा। देश के कुछ हिस्सों में किसानों के लिए साल 2023 जहां चुनौतीपूर्ण रहा वहीं कुछ अच्छा भी हुआ। एक तरफ जहां किसान भाइयों ने मौसम की मार झेली या कीट.पतंगों से उन्हें लड़ना पड़ा तो वहीं नई कृषि तकनीक और आर्थिक मदद से राह आसान भी हुई।

साल 2023 कृषि से जुड़ी नई योजनाओं और प्राकृतिक मार दोनों के लिए याद किया जाएगा। देश के कुल 718 जिलों में से 500 से अधिक जिले वर्तमान में मौसम संबंधी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इन जिलों मे हल्के शुष्क से लेकर अत्यधिक शुष्क के हालात हैं। फिर भी कई किसान सही सूझ बूझ से नए साल में कुछ नया करने की तैयारी में हैं। इसकी एक वजह गुजरे साल की कुछ अच्छी बातें भी हैं।

20 लाख किसानों को मिले क्रेडिट कार्ड

गुजरे साल में 20 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का तोहफा मिला। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। यह देश की सबसे कम ब्याज दर वाले लोन स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को शॉर्ट टर्म टेन्योर का लोन मिलता है, ताकि किसान अपनी अचानक वित्तीय जरूरत को पूरा कर सकें। इसका एक फायदा ये भी है कि किसानों को इस स्कीम के तहत जो लोन मिलता है, उसमें उन्हें ज्यादा ब्याज भी नहीं देना पड़ता, उन्हें कहीं कम ब्याज पर लोन मिल जाता है।

कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा

गुज़रा साल ड्रोन के नाम भी रहा। देश में एग्री सेक्टर में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के मकसद से सरकार कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को ड्रोन की खरीदी पर भारी सब्सिडी के साथ ही ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसी कड़ी में फर्टिलाइजर कंपनी इफको कृषि ड्रोन खरीद के ग्रामीण इलाकों के चुनिंदा उद्यमियों को सौंप रही है। इनका इस्तेमाल उर्वरक और रसायन छिड़कने के लिए किया जा रहा है।

साल 2023 में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए देश भर में श्री अन्न योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार मोटे अनाज यानी श्री अन्न पर ख़ास जोर दे रही है। इसी कड़ी में, यूपी सरकार ने नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच 3 माह में मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 5.82 लाख मीट्रिक टन कर दिया । इसमें सबसे ज्यादा 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई। जबकि 30 हजार टन ज्वार, 50 हजार टन मक्का और 2 हजार टन कोदो की खरीद आगे भी की जाएगी।

गुजरे साल में किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सात दशक पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया । सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी। आजादी से पहले भारत में राजस्व, कृषि एवं वाणिज्य विभाग था, जिसकी स्थापना जून 1871 में हुई थी। इसके बाद 1881 में इसे पुनर्गठित कर राजस्व एवं कृषि विभाग को अलग कर दिया गया, लेकिन 1923 में शिक्षा और स्वास्थ्य को इसमें शामिल कर. शिक्षाए स्वास्थ्य और भूमि.कर दिया गया। बागवानी के लिए 2,200 करोड़ साल 2023 में बागवानी के लिए 2,200 करोड़ की राशिन आवंटित की गई प् सरकार ने 2,200 करोड़ रुपये से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया । गुजरे साल में बागवानी से जुड़े किसान भाइयों के लिए ये बड़ी मदद रही। मत्स्य सम्पदा की नई उपयोजना पीएम मत्स्य सम्पदा की नई उपयोजना के जरिए 6000 करोड़ खर्च किया जायेगा। गुजरे साल में इससे जुड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए देश में मछली का उत्पादन बढ़ाने की शुरुआत 2023 से की गई। सरकार की तरफ से इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए 20,050 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 17000 करोड़ से किया है। निर्धारित धनराशि का उपयोग सरकार द्वारा 2021 और 2025 तक किया जाएगा।

जैविक खेती को बढ़ावा

प्राकृतिक खेती के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्र प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोले जा रहे हैं। गुज़रे साल में जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोलने का फैसला अहम् कदम था। ये केंद्र किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लिए जरुरी जैव.संसाधनों तक आसान पहुंच में सहायक हैं। गाय का गोबर और मूत्र, नीम और अन्य प्राकृतिक इनपुट इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। ये जैव.इनपुट संसाधन केंद्र रणनीतिक रूप से प्राकृतिक खेती के प्रस्तावित 15,000 मॉडल समूहों के साथ स्थित हैं, जिससे यह तय होता है कि किसानों को उन संसाधनों तक पहुंच है जिनकी उन्हें जरूरत है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना पर गुजरे साल में ख़ास जोर दिया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार द्वारा जैविक खेती के लिए 50000 प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि में से 31000 प्रति हेक्टेयर की राशि जैविक उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों के लिए दिए किए जाएंगे।

एमएसपी में बढ़ोतरी

किसानों की तरफ से उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलना बड़ी शिकायत थी। साल 2023 में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024.25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोत्तरी की हैख ताकि उत्पादक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकें। जौ और चने के लिए क्रमशः 115 रुपए प्रति क्विंटल और 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

घरेलू उत्पादो को दिया बढ़ावा

सरकार की तरफसे घरेलु उत्पादन को बढ़ावा देने पर अब जोर दिया गया है। खाद्य तेल की आधे से अधिक घरेलू मांग आयात के जरिये पूरी की जाती है और यह दुनिया में पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। सभी आयातित खाद्य तेलों में, पाम तेल की हिस्सेदारी लगभग 57 प्रतिशत है, इसके बाद सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत और सूरजमुखी की 14 प्रतिशत है। भारत ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात करता है, जबकि सोयाबीन तेल का बड़ा हिस्सा अर्जेंटीना और ब्राजील से आता है। रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल आयात होता है।

मूल्यवर्धन और वितरण के लिए 8800 की रकम दी जाएगी। किसानों को वित्तीय मदद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। साल 2023 में खास जोर दिया गया। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर तीन.तीन किस्तों में दी जाती है। फिलहाल, किसानों के खाते में अब तक 15 किस्त ट्रांसफर की जा चुकी हैं।

बजट में कई बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023.24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े एलान किए। सरकार ने इस दौरान किसानों को 20 लाख करोड़ तक कर्ज़ बांटने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा की इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। किसान, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। इससे आधुनिक तकनीक को भी बढ़ाया मिल सकेगा। साल 2024 में किसानों को क्या मिलेगा ख़बर है कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने के साथ किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए नए साल में अपना खज़ाना खोलने की तैयारी में है। इसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार की जगह 9 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही फसलों की बीमा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। सरकार इसके लिए आगामी बजट में बड़ा आवंटन करने वाली है। सरकार 2024.25 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है। यह चालू वित्तवर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये से करीब 39 फीसदी ज्यादा होगा। इस फंड की मदद से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ फसल बीमा का दायरा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

प्रदेश में 41.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता

हलधर किसान। मध्यप्रदेश में वर्तमान में जल.संसाधन विभाग के तहत 41 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रहा है। विभाग ने आगामी तीन सालो में इसे बढ़ाकर 53 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को साल दर साल बढ़ाया जाएगा।

2027 तक 53 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य

दिसम्बर.2024 तक 43 लाख हेक्टेयर, दिसम्बर.2025 तक 46 लाख हेक्टेयर और दिसम्बर.2027 तक 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाये जाने का खाका तैयार किया गया है।

जल.संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 40 वृहद, 63 मध्यम और 375 लघु परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 30 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान स्थिति में 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आंशिक सिंचाई सुविधा विकसित की जा चुकी है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। प्रदेश में पानी के अधिकतम उपयोग के लिये सूक्ष्म दाब सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिये 40 वृहद और 53 मध्यम परियोजनाओं में दबावयुक्त पाइप सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए निर्माण किया जा रहा है।

जल.संसाधन विभाग के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में निर्मित सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जल.संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2023.24 में खरीफ फसल के लिये 3 लाख हेक्टेयर, ग्रीष्मकालीन फ्सल के लिये 83 हजार हेक्टेयर एवं रबी फसल के लिये निर्धारित लक्ष्य का 34.17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के संकल्प को विभाग द्वारा पूरा किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

युवा किसान ने जैविक तरीके से तैयार कि तुअर की फसल, 1 एकड़ में देती है 70 क्विंटल उत्पादन

रसायनिक नही जैविक खेती की ओर कर रहे रुख उच्च शिक्षित युवा

मप्र के खरगोन जिले के एक युवा किसान रजत डंडीर ने शहर से करीब 10 किमी दूर स्थित हवाई पट्टी से सटे अपने खेत पर देसी अरहर की एक ऐसी प्राजाति संरक्षित की है, जिसे वे जैविक तरीके से तैयार कर रहे है। इस फसल की खासियत है कि यह निमाड़ी किस्म की देसी तुअर के मुकाबले तीन गुना अधिक उत्पादन देने के साथ ही इसमें कीट- पतंग सहित अन्य रोग लगने की आशंका कम होती है। इस अरहर से एक साल में एक एकड़ रकबे में करीब 70 क्विंटल उत्पादन का अनुमान लगाया है, हालांकि शुरुआत आधे एकड़ खेत से की है। रखरखाव में लागत भी कम।

डंडीर संपन्न कृषक परिवार से ताल्लुक रखते है। उन्होंने एमएससी तक पढ़ाई के बाद नौकरियों की तलाश में न जाकर अपनी पारंपरिक खेती में हाथ बंटाना शुरु किया है और अब वे अपने खेत में प्रयोग के तौर पर कई नवाचार कर रहे है। इसमें पिता सहित परिवार के अन्य लोग भी उसके इस प्रयास में सहयोग दे रहे है। रजत ने अपने विशाल खेत के आधा एकड़ क्षेत्र में जैविक तरीके से महाराष्ट्र से लाया 5 किलो तुअर का बीज लगाया है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। खेत में करीब 8 फीट ऊंची फसल लहलहा रही है। डंडीर ने बताया यह बीज उन्होंने अपने परिचित के खेत में लहलहाती फसल देखकर बुलावा।

निमाड़ीकिस्म से अलग वैरायटी है यह तुअर

डंडीर ने अपने खेत में जो बीज लगाया है वह देसी तुअर से अलग वैरायटी है। महाराष्ट्र से बुलवाया यह बीज टी- 50 नाम से जाना जाता है, जिसका उत्पादन में दाना लाल होने के साथ ही देसी तुअर से अधिक उत्पादन देता है। फली में मोटा दाना होने के साथ ही 5 से 6 दाने होते है जबकि देसी तुअर में 3 से 4 दान वह भी कम आकार के होते है। वही पौधे में देसी तुअर का फूल पीला होता है जबकि महाराष्ट्र के बीच का दाना लाल है।

5किलो बीज में 35 क्विंटल उत्पादन का अनुमान

डंडीर ने बताया कि फसल अब पककर तैयार होने की स्थिति में है। उन्हें अनुमान है कि करीब 35 क्विंटल से अधिक उत्पादन होगा। बाजार में जैविक उपज का दाम फिलहाल 11 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। डंडीर ने बताया कि जैविक फसल का बाजार में दाम अच्छा मिलने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए लाभ दायक होने के चलते वह अपने खेत में जैविक तरीके से फसल उत्पादन का प्रयास कर रहे है। सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने तुअर फसल में रसायनिक खादो का उपयोग न करते हुए जैविक तरीके से दवाईयां बनाकर छिडकांव किया है। नीम तेल, गुड, गौमूत्र से खुद दवाईयां तैयार की और खेत में इस्तेमाल करते हैं। जैविक तरीके से तरह.तरह के फसलों से होने वाले आय से किसानों की आमदनी दोगुनी होने का सपना साकार हो सकता है।

बगीचा भी कर रहे तैयार

डंडीर ने अपने 110 एकड़ के विशाल खेत में कई तरह के प्रयोग किए है। वर्तमान में वे बगीचे का निर्माण भी कर रहे है, जिसमें इंडोनेशिया से लाए जाम, बैंगलौर का आम का पौधा भी लगाया है। इनकी खासियत यह है कि महज 1 साल के भीतर यह पौधे फल देने लगे है, इनकी ऊंचाई भी महज 4 से 6 फीट है। डंडीर ने बताया किसान हाईब्रिड और विदेशी बीजों का खेल समझ गए हैं। वो अब देसी बीज ही अपना रहे हैं क्योंकि चाहे पानी ज्यादा बरसे या सूखा पड़े हमारे देसी फसल तैयार हो जाती है लेकिन हाईब्रिड बीज वाली फसलें मौसम में ज्यादा अंतर आने पर बर्बाद हो जाती हैं।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।